4 अगस्त 2017

मून-ट्रम्प शिखर सम्मेलन - एक आकलन

*डॉ. जोजिन वी. जॉन**

सारांश

मून-ट्रम्प शिखर सम्मलेन अमेरिका-दक्षिण कोरिया के मजबूत सम्बंधों के एक कदम तथा आगे बढ़ने का गवाह बना, जो इस द्विपक्षीय संबंध को आकार देने के संरचनात्मक कारणों के भारी प्रभाव को दर्शाता है।

अमेरिका-दक्षिण कोरिया ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त बयान जारी किया जो कि 6 विषयों पर केंद्रित रहा। इस शिखर सम्मलेन की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर कोरिया नीति पर "लॉक-स्टेप कोऑर्डिनेशन" समझौते पर पहुंचना रहा।

दोनों नेताओं ने उत्तर कोरिया से बातचीत में सियोल की अहम भूमिका पर भी सहमति जताई। ये कदम बताता है कि उत्तर कोरिया से निपटने के लिए अमेरिका को न केवल अपनी सीमित शक्ति का अहसास हो गया है बल्कि उसे कुछ नए तरीकों की तलाश भी है।

आर्थिक संबंधों पर ट्रम्प द्वारा की गई आलोचना सियोल तथा वॉशिंगटन के बीच वैचारिक तथा संस्थागत अंतर के साथ दीर्घावधि में नकारात्मक संबंधों की संभावना को दिखाती है।

इस शिखर सम्मलेन के परिणाम ने बढ़ती असुरक्षा के बीच अपने देश को आगे बढ़ाने में राष्ट्रपति मून की सीमाओं को भी दर्शाया है।

शिखर सम्मेलन में घरेलू राजनीतिक मजबूरियां देखने को मिलीं। राष्ट्रपति मून ने आंतरिक आलोचना से बचने के लिए अपना ध्यान अमेरिकी आश्वासन तथा समर्थन पर

केंद्रित रखा। व्यापार समझौते पर पुन: मध्यस्थता एवं गठबंधन के बोझ पर ज़ोर देते हुए ट्रम्प अपने घरेलू निर्वाचन क्षेत्र से 'अमेरिका पहले' वाले दृष्टिकोण के सामंजस्य के साथ अपील करते दिखे।

प्रस्तावना

वॉशिंगटन में 29-30 जून 2017 को दक्षिण कोरिया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ पहला शिखर सम्मेलन हुआ। मून-ट्रम्प शिखर सम्मेलन कई मायनों में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। ये राष्ट्रपति मून की पहली विदेश यात्रा थी। उन्होंने मई 2017 में राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। ऐसे में नए प्रशासन की विकसित विदेश नीति तथा अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन पर उनके दृष्टिकोण की प्रारम्भिक झलक देखने को मिली। दूसरा, इस शिखर सम्मेलन ने ट्रम्प तथा मून के शासनकाल में अमेरिका-दक्षिण कोरिया के संबंधों का एक नया अध्याय शुरू किया। इसने संचार के उन माध्यमों को भी बहाल किया जो सियोल में राजनीतिक पक्षाघात के दिनों के दौरान खो गए थे, विशेषकर तब, जब द्विपक्षीय संबंधों में उदासीनता दिखने लगी थी। तीसरा, मून ने कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा संकट तथा एक अनिश्चित क्षेत्रीय रणनीतिक क्रम को देखते हुए वॉशिंगटन की अपनी यात्रा का कार्यक्रम जल्दी रखा। उभरता हुआ मून-ट्रम्प समीकरण क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक प्रमुख कारक है।

नए सन्दर्भ में अमेरिका-दक्षिण कोरिया सम्बंध

अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया में 2017 में आए राजनीतिक बदलाव, चीन के साथ तनावपूर्ण सम्बंध तथा उत्तरी कोरिया की उग्र मौजूदगी ने अमेरिका-दक्षिण कोरिया के सम्बंधों को एक नया संदर्भ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प तथा दक्षिण कोरिया में मून जे-इन के निर्वाचन ने दोनों देशों के सम्बंधों में अनिश्चितता तथा तनाव की स्थिति पैदा कर दी थी। दोनों देशों का नया नेतृत्व अपने देश की विदेश नीति में परिवर्तन के वादे के साथ सत्ता में आये थे। ऐसे में सियोल तथा वॉशिंगटन की बदलती विदेश नीति की अस्पष्टता तथा ट्रम्प-मून के वैचारिक एवं व्यक्तित्व के अंतर ने अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान पैदा कर दिए थे।

नेतृत्व के व्यक्तित्व के अलावा, तीन घटनाओं ने शिखर सम्मलेन से पहले अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन के भविष्य को लेकर तमाम आशंकाएं बढ़ा दी थीं। सबसे पहले, राष्ट्रपति मून का प्रक्रियात्मक समस्या तथा पर्यावरण का हवाला देते हुए दक्षिण कोरिया में टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस (THAAD) मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती को निलंबित करने का निर्णय। इसे अमेरिका ने चीन के प्रभाव में आकर लिया गया निर्णय बताया तथा दोनों देशों के सम्बंधों के लिए विश्वासघात करार दिया। दूसरा, सियोल तथा वाशिंगटन के बीच उत्तर कोरिया को लेकर नीतियों में भिन्नता, राष्ट्रपति मून का सहभागिता नीति का ऐलान तथा सैन्य धमकी के साथ राष्ट्रपति ट्रम्प की "अधिकतम दबाव तथा वार्ता" की नीति। तीसरा, राष्ट्रपति ट्रम्प के दक्षिण कोरिया को एक 'मुफ्त सवार' के रूप में देखने, व्यापार समझौते में परिवर्तन तथा सियोल पर सुरक्षा के लिए अधिक भुगतान पर जोर ने द्विपक्षीय संबंधों में तनाव उत्पन्न कर दिया। इसके बाद दक्षिण कोरिया में गठबंधन को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा।

मून-ट्रम्प शिखर सम्मलेन का परिणाम

मून-ट्रम्प शिखर सम्मेलन ने दक्षिण कोरिया में अधिक ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अमेरिकी मीडिया में इसे बहुत कम कवरेज मिली। राष्ट्रपति मून, जो पहली बार वॉशिंगटन आए थे, उन्होने विभिन्न कार्यक्रमों में अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन पर एक भावनात्मक बयान दिया। इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे वो एक व्यक्ति के रूप में तथा कोरिया एक देश के तौर पर अमेरिका का ऋणी है।

ट्रम्प तथा मून के बीच विकसित सौहार्दपूर्ण संबंध इस शिखर सम्मेलन का एक बड़ा परिणाम था। शिखर सम्मेलन से पहले दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व तथा वैचारिक नीतियों में अंतर के चलते जताई जा रही चिंताओं को देखते हुए ये एक महत्त्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है। इस शिखर सम्मेलन के बाद एक साझा बयान जारी किया गया, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए 6 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। गठबंधन की मजबूती, उत्तर कोरिया के लिए दृष्टिकोण, व्यापार, व्यापार के अलावा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, अमेरिका-दक्षिण कोरिया वैश्विक साझेदारी तथा गठबंधन का भविष्य जैसे मुद्दे चर्चा का विषय रहे।

ये संयुक्त बयान अमेरिकी-दक्षिण कोरिया गठबंधन में एक महत्त्वपूर्ण निरंतरता को दर्शाता है। इसने दोबारा पुष्टि की, कि "दक्षिण कोरिया की रक्षा", "दक्षिण कोरिया पर युद्ध समय के संचालन नियंत्रण की स्थिति आधारित हस्तांतरण", "शांतिपूर्ण तरीके से कोरियाई प्रायद्वीप का पूर्ण, निरीक्षण तथा अपरिवर्तनीय परमाणु मुक्तिकरण", "उत्तर कोरिया में मानवाधिकार के उल्लंघन पर चिंता" तथा क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका-दक्षिण कोरिया-जापान के बीच त्रिपक्षीय सहयोग का महत्त्व जैसे मुद्दे अमेरिका की प्रतिबद्धता हैं।

पिछले शिखर सम्मेलनों की तुलना में, मून-ट्रम्प के संयुक्त बयान में भाषा तथा सामग्री को लेकर महत्त्वपूर्ण बदलाव दिखे। इसके विश्लेषण से अमेरिका-दक्षिण कोरिया संबंध में हुए विकास को देखा जा सकता है।

इस शिखर सम्मलेन में सियोल में युद्धकालीन संचालन नियंत्रण के स्थानांतरण के लिए जो शर्त रखी गई, वो ये कि कोरिया "किल चेन, कोरिया एयर तथा मिसाइल डिफेन्स सिस्टम तथा दूसरे गठबंधन प्रणालियों के द्वारा" महत्त्वपूर्ण रक्षात्मक क्षमता प्राप्त करे। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि THAAD का कोई भी संदर्भ नहीं दिया गया, जिसे रक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रणाली के रूप में विवादित तौर पर जाना जाता है। संयुक्त बयान में THAAD के उल्लेख से होने वाले नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए 'अन्य गठबंधन प्रणाली' का संदर्भ देना एक चाल भर है। हालांकि अमेरिका को इसे लेकर काफी आशंका है। ये समझौता राष्ट्रपति मून के अनुरोध पर किया गया, जो THAAD की तैनाती पर स्पष्ट स्थिति नहीं रखते। वास्तव में, राष्ट्रपति मून ने वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस को समझाने का प्रयास किया कि वे THAAD की तैनाती के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन "लोकतांत्रिक प्रक्रियात्मक वैधता की मांग" में पीछे रह गए हैं। उन्होंने चीन को इसकी वजह मानने से खारिज करते हुए कहा कि THAAD एक "संप्रभुता का मामला है" तथा, "चीन के लिए अनुचित हस्तक्षेप करना उचित नहीं है"।

इस शिखर सम्मेलन की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि दोनों देशों ने उत्तर कोरिया के साथ अपने दृष्टिकोण का समन्वय करने के लिए समझौता किया, जिसमें "परमाणु मुक्तिकरण पर बातचीत के लिए आवश्यक स्थिति बनाने के तरीके" शामिल हैं। हालांकि,

सर्वसम्मति तक पहुंचने के लिए राष्ट्रपति मून ने राष्ट्रपति ट्रम्प की 'अधिकतम दबाव तथा बातचीत' की नीति के प्रति अपना दृष्टिकोण संरेखित किया। यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति मून ने शिखर सम्मलेन से पहले मीडिया साक्षात्कार तथा भाषणों के माध्यम से लगातार इस बात को स्थापित करने के प्रयास किए थे कि वो उत्तर कोरिया को लेकर ट्रम्प के साथ हैं। हालांकि ऐसा करने में, वो काफी हद तक बिना शर्त बातचीत करने की अपनी नीति से दूर चले गए। मून के दृष्टिकोण में परिवर्तन सुरक्षा को लेकर सियोल की भेद्यता तथा विशेष रूप से उत्तरी कोरियाई समस्या को स्वतंत्र रूप से सुलझाने में उसकी सीमाओं को रेखांकित करता है।

"कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण, निरीक्षण योग्य तथा अपरिवर्तनीय परमाणु मुक्तिकरण के साझा लक्ष्य" को प्राप्त करने पर दोनों नेताओं ने एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। इसका अर्थ है "वर्तमान स्वीकृति को लागू करना तथा अधिकतम दबाव के लिए बनाए गए उपायों को लागू करना" जबकि "सही विकल्प के तहत" संवाद का विकल्प खुला रखना। संयुक्त बयान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि दक्षिणी कोरिया तथा अमेरिका दोनों प्रतिबंधों को एक "कूटनीति के उपकरण" की तरह देखते हैं, ताकि उत्तर कोरिया को बातचीत के विकल्प तक लाया जा सके। हालांकि, बिना ये बताए कि सही हालत क्या है, संयुक्त बयान के शुरूआती बिंदु में "सही स्थिति" का उल्लेख अस्पष्ट है। इस तरह से दोनों दल "सही स्थिति" पर अपने-अपने दृष्टिकोण का हवाला देते हुए भविष्य में एक दूसरे से सहमत या असहमत हो सकते हैं। राष्ट्रपति मून ने शिखर सम्मलेन के बाद वॉशिंगटन के सामरिक तथा अंतरराष्ट्रीय अध्य्यन केंद्र में दिए गए अपने भाषण में "सही स्थिति" पर अपने पक्ष का संकेत दिया। उनके लिए बातचीत के लिए सही स्थिति तब हो सकती है; "जब उत्तर कोरिया अपने परमाणु तथा मिसाइल कार्यक्रमों को रोकने का वादा करे" या "जब उत्तर कोरिया बंदी बनाए गए अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दे"।

"कोरियाई प्रायद्वीप के शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए एक माहौल को प्रोत्साहन देने में सियोल की प्रमुख भूमिका" तथा "मानवतावादी मामलों सहित कई मुद्दों पर अंतर-कोरिया संवाद को पुनः आरंभ करने" की नए प्रशासन की योजना को ट्रम्प की मान्यता इस शिखर सम्मेलन की एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

अमेरिका के लिए समर्थन तथा सुरक्षा प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर मून को घरेलू मोर्चे पर काफी लाभ मिला है। मून अपने देश में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कमजोर होने के लिए रूढिवादियों

की आलोचना का शिकार होने से बच जायेंगे तथा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में होंगे। कोरियाई नेशनल असेंबली में बहुमत नहीं होने की घरेलू राजनीतिक मजबूरी ने राष्ट्रपति मून को सुरक्षा मुद्दों के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। वॉशिंगटन की ओर से अंतर-कोरिया संबंधों को आगे बढ़ाने में सियोल की अग्रणी भूमिका को मान्यता, मून के प्रगतिशील समर्थन के आधार के लिए काफी बेहतर होगा, जो उत्तर कोरिया से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को प्रभारी तौर पर देखना चाहते हैं। संक्षेप में, शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरुप राष्ट्रपति मून रूढ़िवादिता तथा प्रगतिशीलता के बीच उत्तर कोरिया को लेकर वर्तमान मतभेद का सामना करने से बच गए हैं।

शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी पर हितों के मतभेद भी सामने आए। आर्थिक सम्बंधों में टकराव वैचारिक असहमति को रेखांकित करता है जो वाशिंगटन में राजनीतिक बदलाव को दर्शाती है। पिछले दो दशकों के दौरान मुक्त बाजार में साझा विश्वास अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन को मजबूती देने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक रहा है। ट्रम्प के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बंधों के प्रति संरक्षणवादी दृष्टिकोण ने द्विपक्षीय आर्थिक सम्बंधों में स्थिरता से एक वैचारिक बाधा का निर्माण किया है। पिछले संयुक्त बयान में एक प्रमुख विषय के रूप में शामिल 'मुक्त बाजार सिद्धांत' को इस बार मून-ट्रम्प घोषणापत्र में कोई स्थान नहीं मिला। दक्षिण कोरियाई सूत्रों के अनुसार संयुक्त बयान जारी करने में सात घंटे का विलंब दक्षिण कोरियाई प्रस्ताव में व्यापार संबंधों के संदर्भ में "मुक्त" शब्द के प्रयोग पर अमेरिका की अस्वीकृति के कारण हुआ।

संयुक्त बयान में व्यापार के मुद्दे पर ट्रम्प की चिंताओं को स्वीकार किया गया तथा 'संतुलित', 'पारस्परिक' एवं 'निष्पक्ष व्यापार' सुनिश्चित करने के लिए दोनों ने प्रतिबद्धता जताई। हालांकि वो उपाय क्या होंगे, इनका जिक्र संयुक्त बयान में नहीं है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, राष्ट्रपति ट्रम्प ने व्यापार समझौते पर पुन: बातचीत की मांग की। वास्तव में, उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों ने शिखर सम्मेलन में व्यापार समझौते पर पुन: बातचीत करने पर सहमति जताई है। हालांकि, राष्ट्रपति मून ने बाद में दावा खारिज कर दिया। शिखर वार्ता के बाद अमेरिका द्वारा व्यापार समझौते पर पुनर्विचार करने के प्रस्ताव के साथ दक्षिण कोरिया को एक औपचारिक अधिसूचना भेजी गई है।

सियोल की रक्षा के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हुए ट्रम्प ने कहा कि उनका प्रशासन "दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के समर्थन में निष्पक्ष

बोझ को साझा करने के लिए" काम कर रहा है। इस मुद्दे पर ट्रम्प का विचार है की अमेरिकी सेना की तैनाती सीधे उन राष्ट्रों की रक्षा में योगदान दे रही है। लिहाजा उन्हें गठबंधन की लागतों का अधिक भुगतान करना चाहिए। अपने चुनाव अभियान के समय से ट्रम्प दक्षिण कोरिया पर "मुफ्त सवार" होने का आरोप लगा चुके हैं तथा दक्षिण कोरिया को अपनी सुरक्षा के लिए अधिक भुगतान करने की मांग कर चुके है। हालांकि, संयुक्त बयान में इस मुद्दे का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रम्प द्वारा इस पर जोर दिया जाना बताता है कि आने वाले वक्त में द्विपक्षीय संदर्भ में यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा होगा।

शिखर सम्मेलन में यह बिलकुल स्पष्ट था कि द्विपक्षीय सम्बंधों का आर्थिक आयाम आसान नहीं है। शिखर सम्मेलन के परिणाम से ये स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा संकट की स्थिति का सामना कर रहे राष्ट्रपति मून, राष्ट्रपति ट्रम्प के दबाव में हैं। संयोग से, इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरिया अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक आर्थिक पैकेज लेकर आया था। इस पैकेज में कोरियाई कंपनियों का अमेरिका में 12 अरब डॉलर का निवेश तथा अमेरिका से 25 अरब डॉलर का प्राकृतिक गैस खरीदने का एक समझौता शामिल है।

निष्कर्ष

मून-ट्रम्प शिखर सम्मेलन आशा से अधिक बेहतर रहा। बढ़ते सुरक्षा तनाव की स्थिति ने अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन की निरंतरता सुनिश्चित की। शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति मून ने अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन ढांचे के भीतर उत्तर कोरिया से निपटने के लिए सियोल की भूमिका को बढ़ाया तथा अपनी नीति से अमेरिकी समर्थन हासिल करने में सफल रहे। हालांकि, अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन का भविष्य चुनौती भरा है। फिर भी दोनों नेताओं ने दबाव तथा सहभागिता का उपयोग करते हुए उत्तर कोरियाई परमाणु मुद्दे पर "लॉक-स्टेप कॉर्डिनेशन" पर सहमति व्यक्त की। लेकिन कितना दबाव तथा किस स्थिति में सहभागिता निभाई जाएगी, इस बात पर कोई सहमति नहीं जताई गई है। राष्ट्रपति मून भले ही कुछ वक्त के लिए THAAD के मुद्दे को पर्दे के पीछे रखने में सफल रहे, लेकिन चीन से बढ़ते दबाव के बाद राष्ट्रपति मून के लिए THAAD पर उनकी अस्पष्ट स्थिति को पीछे छिपाना आसान नहीं होगा।

मून-ट्रम्प ने उत्तर कोरिया पर जो भी सहमति व्यक्त की, उससे अधिक, उनका दृष्टिकोण अमेरिका-चीन संबंधों में विकास पर निर्भर होगा। उत्तर कोरिया को लेकर चीन तथा अमेरिका में समन्वय न होने की वजह से दक्षिण कोरिया के लिए अपनी सहभागिता नीति को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। हाल ही में वॉशिंगटन द्वारा दोबारा लगाए गए प्रतिबंधों का बीजिंग तथा मास्को पहले ही विरोध कर चुके हैं, जो प्योंगयांग पर और अधिक प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध हैं।

आर्थिक संबंधों तथा गठजोड़ के बोझ को साझा करने को लेकर भिन्न परिप्रेक्ष्य भी महत्त्वपूर्ण कारक हैं। इन मुद्दों पर दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका के बीच मतभेद अभी केवल उभर रहे हैं तथा द्विपक्षीय संबंधों पर उनके प्रभाव को देखा जाना अभी बाकी है।

**डॉ. जोजिन वी. जॉन, विश्व मामलों की भारतीय परिषद में शोध अध्येता हैं।*

**डिस्क्लेमर: उपरोक्त आलेख में दिये गए विचार शोध अध्येता के निजी विचार हैं तथा परिषद के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते।*